भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1991

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मधुमेह के बढ़ते मामले

†1991. श्री बैन्नी बेहनन:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर उन राज्यों में जहां मधुमेह के रोगियों की संख्या ज्यादा है, मधुमेह के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विश्व में अनुपचारित मधुमेह के 30 प्रतिशत मामले भारत से होते हैं और यदि हां, तो इस संबंध में उपचार की पहुंच में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में मधुमेह की रोकथाम के लिए जीवनशैली में बदलाव करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है अथवा योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो अभियानों सहित उनकी पहुंच और प्रभाव आकलन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उपयुक्त स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र को रेफर करने और स्वास्थ्य संवर्धन तथा जागरूकता सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, 753 जिला एनसीडी क्लीनिक और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत, देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में मधुमेह सहित सामान्य एनसीडी की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल के अनुसार, 30 नवंबर 2024 तक, मधुमेह के संबंध में **32.33 करोड़** लोगों की **जांच** की गई, **2.96 करोड़** लोगों का **निदान** किया गया और **3.13 करोड़** लोगों का मधुमेह का उपचार किया गया। (राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-क** में दी गई है)।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि विश्व में अनुपचारित मधुमेह रोगियों में से 30 प्रतिशत रोगी भारत से हैं। https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02317-1/fulltext); लिंक पर हाल ही के प्रकाशन में प्रकाशित आंकड़ों में केवल एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर लोगों को शामिल किया गया और जीवनशैली में बदलाव और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों पर निर्भर सभी लोगों को इसमें शामिल नही किया गया। इसमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्हें मधुमेह है। एनएचएम की निशुल्क औषधि पहल के अंतर्गत, सभी जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मधुमेह सहित अनिवार्य औषधियां निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का उद्देश्य, भारत की आबादी के निचले 40% के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में, योजना के तहत सूचीबद्ध 29,870 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से मधुमेह, और मधुमेह के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलताओं सहित 27 विशिष्टताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मधुमेह से उत्पन्न जटिलताओं से संबंधित कुछ पैकेज डायबिटिक फुट, डायबिटिक केटोएसिडोसिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी आदि हैं।

इसके अलावा, मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली के संवर्धन के लिए किए गए उपायों में विश्व मधुमेह दिवस मनाना, निरंतर सामुदायिक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है। मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों के लिए जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के ईट राइट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से स्वस्थकर भोजन को बढ़ावा दिया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा "फिट इंडिया मूवमेंट" लागू किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

अनुलग्नक क - 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल के अनुसार मधुमेह के संबंध में की गई जांच, निदान, उपचार की राज्यवार सूची

राज्य	की गई जांच	किए गए निदान	उपचाराधीन
पैन इंडिया	**32,33,32,732**	**2,96,26,225**	**3,13,97,907**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69,026	16,288	16,263
अरुणाचल प्रदेश	85,696	4,894	4,885
असम	48,85,107	4,84,780	4,84,774
बिहार	2,21,06,230	2,43,432	2,42,970
चंडीगढ़	3,41,094	21,401	21,330
छत्तीसगढ़	92,12,582	9,39,202	9,32,171
दिल्ली	1,25,212	1,112	1,108
गोवा	2,12,598	90,473	89,950
गुजरात	2,92,81,053	24,04,186	24,01,979
हरियाणा	67,95,930	4,32,376	4,30,213
हिमाचल प्रदेश	30,52,860	2,04,034	2,04,034
जम्मू और कश्मीर	43,18,708	3,41,071	3,40,236
झारखंड	37,23,768	53,565	53,271
कर्नाटक	2,37,00,475	28,83,541	28,74,257
लद्दाख	1,22,934	8,768	8,741
लक्षद्वीप	14,701	1,223	1,207
मध्य प्रदेश	2,19,54,953	23,89,724	23,75,604
महाराष्ट्र	2,49,73,153	40,03,484	39,81,750
मणिपुर	1,46,406	23,484	23,354
मेघालय	3,09,322	29,563	29,519
मिजोरम	4,20,682	4,527	4,511
नागालैंड	68,806	22,637	22,127

ओडिशा	1,66,08,189	15,12,414	15,04,728
पुडुचेरी	1,01,821	56,542	56,298
पंजाब	20,51,004	6,73,243	6,67,270
राजस्थान	1,25,16,333	16,21,613	15,96,432
सिक्किम	1,31,601	33,866	33,467
तेलंगाना	1,75,29,700	24,52,989	24,52,989
त्रिपुरा	6,55,590	72,781	72,590
उत्तर प्रदेश	1,93,07,695	2,06,347	2,05,950
उत्तराखंड	19,91,482	80,965	80,797
आंध्र प्रदेश*	3,85,10,834	20,92,505	20,92,505
केरल*	0	47,92,854	0
तमिलनाडु*	5,76,66,670	14,25,409	80,90,626
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव*	3,38,314	961	0
पश्चिम बंगाल*	2,203	1	1
	32,33,32,732	**2,96,26,255**	**3,13,97,907**

* राज्य अपनी स्वयं की एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं और समस्त डेटा राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल पर भेज रहे हैं।

*****